

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)  
 पत्रांक- १२१४ /रेनुकूट/ १५-१८४ दिनांक, रेनुकूट, दिसम्बर, २५ २०२५  
 सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लिंग की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हेक्टेक्टर आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं वाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।  
 (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017)।

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- ८वी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/९९१ दिनांक- २९.०३.२०२३
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- ३१५०/११-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक-३१.०३.२०२३
- 3- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- ६२१/११-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक-२०.०८.२०२५
- 4-क्षेत्रीय महाप्रबन्धक एन०सी०एल० बीना परियोजना, बीना सोनभद्र का पत्रांक-बीना/पर्या./उ०प्र०/वन/२०२५/७७ दिनांक-१७.१२.२०२५

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- २९.०३.२०२३ व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- ३१.०३.२०२३ द्वारा दो बिन्दुओं से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखों की मॉग की गयी :-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- ८वी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/९९१ दिनांक- २९.०३.२०२३ में अंकित बिन्दु।
1	No non -forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .
2	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation

उक्त दोनों बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा एन०सी०एल० बीना परियोजना से अनुरोध किये जाने पर क्षेत्रीय महाप्रबन्धक एन०सी०एल० बीना परियोजना ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या- बीना/पर्या./उ०प्र०/वन/२०२५/७७ दिनांक-१७.१२.२०२५ द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक- १७.०३.२०२५ एवं १७.१२.२०२४ की छायाप्रति संलग्न करते हुये ऑनलाइन प्रस्ताव में अपलोड किये गये ६१.०० हेक्टेक्टर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किये जाने वाले अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक-१७.०३.२०२५ में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है:-

- i. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs
- ii. The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.

भारत सरकार के पत्र दिनांक-१७.१२.२०२४ में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है:-

As per the provisions of the van (sanrakshan evam samvardhan) amendment rules 2024 project of central government entities/ CPSU and captive coal blocks of the state PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. accordingly, the state government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the central government agencies/CPSUs or state government PSUs with

captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the state government/ UT administration is willing to provide non-forest land on such terms and condition which is agreed by the central government agencies/ CPSUs or state government PSUs in case of captive coal blocks.

भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक- 17.12.2024 एवं 17.03.2025 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से भारत सरकार पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन अलीगंज लखनऊ को वस्तु रिस्ति से अवगत कराते हुये उचित दिशा निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी तक कोई निर्देश प्राप्त होने की सूचना प्रभाग के संज्ञान में नहीं है।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर वर्ष 2017 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है, तब से पत्राचार में है। उक्त प्रस्ताव भारत सरकार की परियोजना होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेश दिनांक- 17.12.2024 एवं 17.03.2025 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रभावित वनभूमि 30.50 हेक्टेएर के दोगुने अवनत वनभूमि 61.00 हेक्टेएर पर क्षतिपूरक वनीकरण की योजना सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख जो ऑनलाइन प्रस्ताव में अपलोड किये गये हैं उसके आधार पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दिनांक-17.12.2025 एवं भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक-17.12.2024 एवं 17.03.2025 की छायाप्रति संलग्न करते हुये संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित है।

भवदीय

(कमल कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या-२१५ अ/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लिलो बीना, परियोजना, बीना-सोनभद्र को उनके पत्र संख्या- बीना/पर्या. /उ0प्र0/वन/2025/77 दिनांक-17.12.2025 के क्रम में।

(कमल कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager

CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO45001 Certified Company

बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220  
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclil.in

दिनांक: 17.12.2025

क्र. बीना/ पार्य./उप्र०/ वन/ 2025/ ७७

सेवा में,  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
रेनकूट वन प्रभाग,  
उप्र० वन विभाग

विषय:- जनपद - सोनभद्र में रेनकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हेक्टर भूमि के लिए 61 हेक्टर degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक: 17.12.2024;  
व 17.03.2025

महोदय,  
उपरोक्त विषय के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्रांक 17.03.2025 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें:

- As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs.
- The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 17.12.2024 (प्रति संलग्न) के बिन्दु क्र० - (iv) का भी अवलोकन करने का कष्ट करें:

"As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects of Central Government entities/CPSU and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. Accordingly, the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs with

४५

*"captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provide non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks."*

उपरोक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि Central Public Sector Undertakings के लिए गैर-वन भूमि की अनुपलब्धता को प्रमाणित करने हेतु राज्य सरकार से प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है एवं Central Public Sector Undertakings के लिए दोगुने अवक्रमित वन भूमि (double degraded forest) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) करवाने का प्रावधान उपलब्ध है।

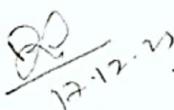
उपरोक्त पत्र से यह भी स्पष्ट है कि राज्य में प्रसंरकरण प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की गाइडलाइन्स दिनांक: 17.12.2024 का पालन किया जा सकता है।

एन०सी०एल० एक Central PSU है तथा इस प्रस्ताव (FP/UP/MIN/24551/2017) हेतु बीना परियोजना के लिए 61 हैं। degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम उपलब्ध है जो कि पूर्व में भारत सरकार प्रेषित कि गयी थी।

अतः आपसे अनुरोध है कि बीना कक्षीय एकीकरण परियोजना में 61 हैं। degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने कि कृपा करें।

संधन्यवाद

भवदीय

  
क्षेत्रीय महाप्रबंधक,  
बीना परियोजना, एन०सी०एल०  
19/2

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (पर्यावरण), एन०सी०एल०, सिंगरौली।

Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,  
Aliganj, Jor Bagh Road,  
New Delhi: 110003  
Dated: March, 2025

To

The Principal Secretary (Forests),  
Government of Maharashtra,  
Mantralaya Mumbai

**Sub: Permitting double the degraded forest land in lieu of non-forest land for certain projects taken up by CPSU / SPSU and other government agencies - reg.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to the State Government of Maharashtra's letter no. FLD-2025/CR-42/F-10 dated 25.02.2025 on the above subject seeking advise from the Ministry on the implementation of the Guidelines related to compensatory afforestation vis-à-vis directions passed by the Hon'ble Supreme Court in its order dated 3.02.2025. In this connection, it is to inform that after examination of the concerns of the State Government, the following is informed:

- i. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evar Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs.
- ii. The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.
- iii. In light of directions contained in the Hon'ble Supreme Court's order dated 3.02.2025 and 4.03.2025, it is further to inform that no forest land should be diverted without compensatory afforestation for which land is to be provided in accordance with relevant provisions provided under the Van (Sanrakshan Evar Samvardhan) Rules, 2023 (as amended) and Guidelines issued thereunder.

This issues with the approval of the competent authority.

Digitally signed by  
CHARAN JEET SINGH  
Date: 17-03-2025  
09:33:49

Yours faithfully,  
(Charan Jeet Singh)  
Scientist 'E'

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, State Government of Maharashtra, Nagpur
2. Dy Director General of Forests (Central), Regional Offices of the MoEF&CC at Nagpur
3. Nodal Officer (Sanrakshan Evar Samvardhan), O/o the PCCF, State

Government of Maharashtra, Nagpur  
4. Guard File.

Subject: Re: Application for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra.

Re: Application for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra.

Dear Sir

It is stated to refer to the above subject, I am pleased to inform you that the application received from the State of Maharashtra, Nagpur regarding the grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur has been received by the Ministry and placed under consideration. In accordance with the provisions of section 3 of the Land Acquisition Act, 1983, Government of Maharashtra, 1983 hereby issues the following directions:

1. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

2. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

3. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

4. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

5. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

6. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

7. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

8. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

9. The application of the State of Maharashtra, Nagpur for grant of permission to construct a building on land held in the name of the State of Maharashtra, Nagpur is hereby accepted.

Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,  
Aliganj, Jor Bagh Road,  
New Delhi: 110003

Dated: December, 2024

To

The Addl. Chief Secretaries of Forests/Principal Secretary (Forests),  
All States Governments and Union territory Administrations

**Sub: Streamlining of the approval process with regards to compensatory afforestation as envisaged in the Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024 – reg.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to the above subject and to inform that based on the references received from the Ministry of Mines, and Ministry of Coal, the provisions related to raising of compensatory afforestation, as envisaged in the Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024, have been reviewed by the Ministry and after due deliberations, the Central Government, in accordance with the provisions of section 3C of the Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 hereby issues the following clarifications:

- i. Provisions of Rule 14(1) of the Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Rules, 2023, provides that the non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation (CA) is to be notified as Protected Forests before final approval (Stage-II) approval is granted by the Central Government. However, in cases where non-forest land identified for CA has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department (SFD), the Central Government may accord final approval keeping in view the fact that provisions of the Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 become applicable on such lands being entered as forest in government record/record of rights.
- ii. In such cases, referred in para (i) above, the non-forest land forest land proposed for CA, shall be notified as Protected Forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 of local forest Act before handing over of forest land to the User Agency by the State Government. The Nodal Officer, after notification of such non-forest lands, shall upload a copy of said notification on the PARIVESH portal.
- iii. For the purpose of rule 13(4)(a) of the States or Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their total geographical area, concerned State Government/UT Administration may authorise a suitable officer to issue certificate of non-availability of the suitable non-forest land for raising CA.
- iv. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects of Central Government entities/CPSU and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. Accordingly, the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the Central Government

Agencies/CPSUs or State Government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provide non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks.

v. With regards to the applicability of the provisions of the Van (Sanrakshan Evar Samvardhan) Amendment Rules, 2024 in respect of proposals of the Central Agencies/PSUs and captive coal blocks of the State PSUs which were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land, the following clarification is given in this regard:

- a. Proposals, which were submitted by the States/UTs before notification of Van (Sanrakshan Evar Samvardhan) Amendment Rules, 2024, along with the proposal of raising CA over degraded forest land (DFL) and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), shall be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL in lieu of NFL. The Central Government will consider and grant final approval in such cases stipulating CA over DFL.
- b. Proposals, which were submitted by the States/UTs along with CA proposal over non-forest land and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), can also be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL provided the non-forest land proposed for CA is not transferred and mutated in favour of the State Forest Department. In such cases, the Central Government or its Regional Office, based on the request of the State/UT Government or user agency, shall amend the condition of in-principle approval to raise CA over DFL on a case to case basis and subsequently the User Agency shall submit the compliance of in-principle for the obtaining the 'final' approval.

In view of the above, the State Government and Union territory Administrations are requested to take into consideration the guidelines mentioned hereinabove while considering the proposals submitted under section 2 of the Van (Sanrakshan Evar Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Signed by

Charan Jeet Singh

(Charan Jeet Singh)

Date: 17-12-2024 13:56:41

Scientist 'E'

Copy to:

1. Director, PMO, South Block, New Delhi
2. Secretary, Ministry of Mines /Coal /Steel/ Power/ Railways/ MoRT&H/ Defence/MHA
3. Secretary, Ministry of Defence, Government of India
4. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, All States Governments and Union territory Administrations
5. Dy Director General of Forests (Central) All Regional Offices of the MoEF&CC

6. Nodal Officers, dealing with the matters related to the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, All States Governments and Union territory Administrations
7. Head, NIC, MoEFCC for aligning the PARIKESH 2.0 as per above